IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत के उत्तर–पूर्व में उग्रवाद की चुनौतियाँ: एक आलोचनात्मक अध्ययन

रश्मि बाजपेयी, शोध छात्रा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय डिग्री कॉलेज,
संघटक महाविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज
डॉ. समीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय डिग्री कॉलेज,
संघटक महाविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

सारांश

इस अध्ययन का उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में मौजूदा अस्थिरता का पता लगाना और प्रभावी रोकथाम के लिये वैकल्पिक नीतिगत सुझाव देना है। ऐसी मान्यता है कि कश्मीर के बाद पूर्वोत्तर भारत देश में सबसे अधिक अस्थिर और उग्रवाद प्रभावित जगह है। पूर्वोत्तर भारत में मुख्यत प्रतिशत सात राज्य, अरुणांचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड तथा त्रिपुरा आते हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्य के पड़ोसी देश, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यामांर तथा चीन से सीमा साझा करते हैं, इस कारण पूर्वोत्तर भारत को 'दक्षिण पूर्व एशिया का द्वार' भी कहा जाता है।

मुख्य शब्द

विप्लव, पूर्वोत्तर, नक्सलवाद, अलगाववाद, उग्रवाद

प्रस्तावना

सिलीगुड़ी गलियारा जो कि चिकेन नेक के नाम से भी जाना जाता है। 60 किलोमीटर लम्बा तथा 22 किलोमीटर चौड़ा पश्चिम बंगाल में स्थित एक संकरा खण्ड है जो कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है और अपनी सूक्ष्म स्थिति के कारण भारत के लिये महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वतंत्रता के समय पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र असम, मणिपुर, त्रिपुरा से मिलकर बना था। इसके बाद 1963 में नागालैण्ड, 1972 में मेघालय तथा 1972 में ही मिजोरम तथा 1987 में अरुणांचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। इसका कुल क्षेत्र 254,645 वर्ग किलोमीटर है।

पूर्वोत्तर भारत के इस क्षेत्र में बहुत सारे जनजातीय समूह अपने भिन्न–भिन्न ऐतिहासिक पृस्ठभूमि के साथ अपने राजनीतिक भविष्य का परिप्रेक्ष्य रखते आये हैं और इसीलिये इस क्षेत्र को अलग–अलग जनजातियों, भाषाओं, संस्कृति, इतिहास के कारण जातीयता का 'मेस्टिंग फॉर 'कहा जाता है अर्थात एक ऐसे समाज का रुप जहां अलग– अलग प्रकार के लोग एक साथ मिल जाते हैं लेकिन भारत जो कि एकता और अखण्डता का अनोखा उदाहरण है कई वर्षो से विप्लव से जूझ रहा है।

भारत विप्लव से क्यों जूझ रहा है इस बात को समझने के लिये विप्लव या विद्रोह की उत्पत्ति को समझना अत्यन्त आवश्यक है। ब्रिटिश लोगों के द्वारा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में गैर हस्तक्षेप की नीति अपनायी गयी और पूर्वोत्तर भारत को केवल कच्चे माल के निर्यातक के रुप में देखा गया।

1947 में जब भारत आजाद हुआ तब इस क्षेत्रों को अपने साथ एकीकृत करना बहुत ही कठिन था। पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न प्रकार की जनजातियों की संस्कृति को जब एक करने की बात आई तब वहाँ ज्यादातर समुदायों ने इसका विरोध

किया। पूर्वोत्तर भारत में विप्लव के कारणों में प्रकाश डाला जाये तब कुछ प्रमुख तथ्य उभर कर सामने आते हैं, जो कि निम्न हैं –

1. जातीय मतभेद।
2. राजनीतिक एवं सरकारी मुद्दे।
3. भौगोलिक चुनौतियों के कारण विश्वास का अभाव।
4. अलगाव, अभाव एवं शोषण की भावना।
5. बाह्य समर्थन।

जातीय मतभेद

भारत के मानव विज्ञान सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 335 जनजातियों में से 213 जनजातियाँ भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवास करती हैं। इनकी संस्कृति, समस्या, पहचान, आकांक्षा भी अलग– अलग रही है। यहाँ कि जनजाति अपनी उत्पत्ति मंगोलायड से मानती है और यह खुद को अनार्य और द्रविण से निम्न मानती है। इसीलिये इनको भारत में एकीकृत करना इनकी विभिन्न पहचान के लिये खतरा रहा है और अपनी इसी संस्कृति को संरक्षित करने के लिये यह लोग विप्लव का सहारा लेते आये हैं।

राजनीतिक एवं सरकारी मुद्दे

पूर्वोत्तर राज्य की राजनीतिक संरचना ज्यादातर भ्रष्टाचार की चपेट में है, कई रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ के राजनेता और विप्लवकारियों के बीच मजबूत सांठगांठ देखने को मिलती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की नौकरशाही और प्रशासन का कम प्रतिनिधित्व और साथ ही साथ स्थानीय निकाय का प्रभावहीन होना इन समस्याओं को और बढ़ा देता है। इस राज्य की खराब संरचना की वजह से लोगों की असुरक्षा बढ़ जाती है। केन्द्रीय प्रशासन से लम्बी दूरी और लोकसभा में कम प्रतिनिधित्व की वजह से लोग अपनी आवाज को नीति निर्माण गलियारों तक नहीं पहुँचा पाते। इसीलिये यहाँ पर विकासशील और प्रतिनिधित्वकारी योजनायें अपनायी जाती हैं और उनमें जमीनी सच्चाई की झलक थोड़ा कम देखने को मिलती है। विप्लवकारी, संघ सरकार की औपनिवेषिक और भेदभावपूर्ण नीतियों को इस क्षेत्र के पिछड़ेपन का कारण मानते हैं। इसके अलावा कई विषेषज्ञ मानते हैं कि आफ्सपा जैसे कानून इस संघर्ष को सैन्य स्तर पर ले जाते हैं। इसके साथ ही इस क्षेत्र को हर साल भयानक बाढ़ देखने को मिलती है जो करोड़ों की सम्पत्ति, लाखों लोगों की जिन्दगी को प्रभावित करती आई है। उच्च वर्षा वाली नदियों के बदलते मार्ग, खराब जल निकासी व्यवस्था और संकीर्ण धारियों के कारण इस क्षेत्र में बाढ़, कटाव, भूस्खलन काफी सामान्य घटनायें हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र को भूमि हानि के अलावा आधारभूत संरचना के नुकसान को भी झेलना पड़ता है। विषेज्ञों के मुताबिक केन्द्रीय सरकार का इसके प्रति कोई संतोषजनक कार्यवाई न करना, सरकार के प्रति लोगों में कटुता पैदा करता है। पहले से कम विकास का दुष्प्रभाव झेल रहे इस क्षेत्र में बांग्लादेश से लाये बड़ी संख्या में शरणार्थी और अवैध अप्रवासियों ने भी विप्लव को बड़े पैमाने पर बढ़ाया है। अवैध अप्रवासी, स्थानीय जनसंख्या के संसाधनों का उपयोग करते हैं जिसकी वजह से सामाजिक सरोकार और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वहाँ के चुनावों में अवैध प्रवासियों के पंजीकृत हो जाने की वजह से स्थानीय लोगों में आक्रोश की भावना जन्म लेती है और इसी अप्रवासन विरोधी शिक्षा ने असम में यूनाइटेड़ लिबरेशन फ्रंट के नेतृत्व में विप्लव को जन्म दिया।

भौगोलिक चुनौतियों के कारण विश्वास का ना हो पाना

पूर्वोत्तर राज्यों की भौगोलिक संरचना भी विप्लव को बढ़ावा देने का प्रमुख एक कारण है। पहाड़ियों की वजह से संचार व्यवस्था का विकास नहीं हो पाया, इस क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग और भारतीय रेल मार्ग की भारी कमी पायी गयी है। इस तरह का अपूर्ण विकास जहाँ एक तरफ यहाँ के लोगों और भारत सरकार के बीच दूरियाँ बढ़ाने का कार्य करता है, वहीं दूसरी तरफ यह विप्लवकारी समूहों के लिये निधि देने के लिये मददगार साबित होता है। यहाँ का घने जंगलों वाला इलाका, मुश्किल मौसम की स्थिति विप्लवकारी समूहों के छिपने के लिये उपयुक्त जगह उपलब्ध कराता है।

उदाहरण के तौर पर असम के विप्लवकारी समूह जैसे उल्फा, असम, भूटान अरुणांचल प्रदेष के जंगली क्षेत्रों में कम सम्पर्क का काफी लम्बे समय से सहारा लेते आये हैं। एक विप्लवकारी समूह अगर एक बार यहाँ शरण से लिया तो फिर सरकार को पता लगाना और मुकाबला करने में सालों साल लग जाते हैं। ऐसी भौगोलिक संरचना में यह समूह अपने 'गुरिल्ला युद्धकला' और 'मारो और भागो' की रणनीति भी अपना पाते हैं और सुरक्षा बल के लिये यह बड़ी चुनौती बन जाती है इसके अलावा इस क्षेत्र की लगभग 4500 किलोमीटर लम्बा अन्तर्राट्रीय सीमा झरझरी है जिसकी वजह से यहाँ

विप्लव को संचालित कर रहे विप्लवकारी म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश आसानी से आ जा पाते हैं और उन्होंने यहाँ पर सुरक्षित स्थान बनाये हुये हैं यह झरझरी सीमाएँ विप्लवकारियों के साथ–साथ अवैध प्रवासन, नशीली दवायें इत्यादि के आदान–प्रदान को भी आसान बना देती है। स्वर्णिम त्रिभुज का पास में होना यहाँ के युवा को नशे का लती बना देता है। खराब कानून व्यवस्था के साथ–साथ इन लोगों की उपस्थिति से विप्लवकारी समूह अपने के लिये इन्हें आसानी इस्तेमाल कर पाते हैं।

अलगाव, अभाव एवं शोषण की भावना

राजनीतिक स्थिरता की कमी और आर्थिक विकास का कुछ हिस्सों में सीमित होना भी इस क्षेत्र की जनसंख्या को प्रभावित करती है। संसाधनों की कमी होने के कारण इस क्षेत्र को केन्द्रीय सरकार की निधि पर निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ पर पारस्परिक कृषि के चलते कम उत्पादकता देखने को मिलती है जो राष्ट्रीय मानक से बहुत कम है। भौगोलिक एवं सेवा क्षेत्र में स्थानीय लोगों का खराब प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। इस कारण यहाँ पर बेरोजगारी और गरीबी दर उच्च देखने को मिलती है और इसी कारण यहाँ का युवा पैसे कमाने के लिये विप्लव और चरमपंथी गतिविधियों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। हमे इस बात को समझना होगा कि आर्थिक विकास के लिये सुरक्षा का होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्षेत्र की 96 प्रतिशत सीमा संवेदनशील अर्न्तराष्ट्रीय सीमा बनाती है इस वजह से यहाँ पर निजी निवेश की भी कमी देखी गयी।

1962 में हुये चीनी आक्रमण के बाद इस क्षेत्र में निजी निवेश की भी काफी कमी देखी गयी है जिसने विकास को काफी पीछे कर दिया। इसके अलावा जब विकास की ओर कदम उठाया जाता है तो आधुनिकीकरण के प्रयास संघर्ष करते हुये दिखाई देते हैं। इन्हीं कारणों से ये राज्य दूसरे राज्यों से पीछे छूट गये हैं और अगर गौर किया जाये तो कई विप्लवकारी समूह इसी भेदभाव की शिकायत करते हुये विप्लव को बढ़ावा देते हैं।

बाह्य समर्थन

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विप्लव को बढ़ावा देने के पीछे एक बड़ी बात अर्न्तराष्ट्रीय सहयोग भी रहा है। 1950 तथा 1660 में पूर्वोत्तर भारत में विप्लव गतिविधि बढ़ाने के लिए पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद ठिकानों में नागा गुरिल्ला को प्रशिक्षित किया करते थे लेकिन बाद में चीन से भी सहयोग मिलना शुरु हो गया, यह सहयोग पिछले 50 सालों से लगातार जारी है। माओ के समय में चीन ने इन समूहों को 15 सालों तक सहयोग दिया और इसकी शुरुआत नागा नेशनल काउन्सिल के चीन के यूनान प्रोत में शरण लेने से हुई। 1959 में दलाई लामा का भारत में आना और भारत–चीन युद्ध के बाद जब भारत–चीन के रिश्तों में कटुता आ गई तब चीन ने नागा और पूर्वोत्तर का खुल कर स्वागत किया लेकिन डेन्गजियोओपिंग के दौर में चीन ने हस्तक्षेप छोड़कर अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने में लग गया और खुला सहयोग करके या हथियारों की तस्करी जारी रखा। 2013 में सिप्री की रिपोर्ट ''चाइनाज स्पोर्ट्स ऑफ स्माल आर्म्स एंड लाइट वेपन्स रिपोर्ट्स'' ने बताया कि दक्षिण पूर्व एशिया के कई बंदूक व्यापारी ब्लैक हाउस एजेन्सी जिनमें चीन के सेना के साथ छोटे शस्त्रों को विद्रोहियों को भेजा करते थे। यह छोटे शस्त्र केवल भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विप्लवकारियों को ही नहीं बल्कि नेपाल के माओवादी और अफगानिस्तान के तालिबानी भी खरीदते थे। इसके अलावा चीन विप्लवकारियों को सुरक्षित ठिकाना भी उपलब्ध कराता था। उदाहरण के लिये उल्फा नेता परेश बरुआ बांग्लादेश में संचालन करता था अब वह चीन के यूनान प्रोत और म्यांमार से के जंगलों के बीच से आंदोलनों को संचालित करता है, इससे जाहिर है कि चीन के मदद के बिना यह संभव नहीं था। चीन इन विप्लवकारियों को भारत के खिलाफ सौदेबाजी चिप की तरह प्रयोग करना चाहता है और इसीलिये वह पूर्वोत्तर क्षेत्र से सम्पर्क ना पूरी तरह से खत्म कर रहा है और ना खुलकर सहयोग कर रहा है। ऊपर से म्यांमार में चीन समर्थन सैन्य शासन, नेपाल, बांग्लादेश चीन का बढ़ता प्रमुख इस जोखिम को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे में भारत को सक्रिय रुप से सीमा अवसंरचना, खुफिया नेटवर्क को सुधार करके विप्लवकारी समूहों को नियंत्रित करने की लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी इसके दशकों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में विप्लव जारी रहा है, लेकिन अब सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिये सक्रिय कदम उठाये हैं। जिन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र में सकारात्मक सुधार किये हैं। उदाहरण के लिये पिछले कुछ समय में 26 क्षेत्र में 120 आतंकवादी समूह संचालन किया करते थे लेकिन पिछले कुछ सालों में सरकार के सैन्य अभियानों की बदौलत इस संख्या सबमें ज्यादा है। जबकि सिक्किम, मिजोरम में न के बराबर। गृह मंत्रालय की एक वर्तमान रिपोर्ट के मुताबिक इस क्षेत्र की सुरक्षा की स्थिति 2014 के बाद काफी हद तक सुधरी है। 2014 की तुलना में विप्लव में 80 प्रतिशत तक कमी आई है। वही सुरक्षा बलों की दुर्घटना में कमी और असैनिक मृत्यु 99 प्रतिशत कमी देखी गयी है।

भारत के आजादी के 75 प्रतिशत वर्ष पूरे हो गये लेकिन इसका जश्न मनाते हुये हमारे लिये यह याद रखना जरुरी है कि भारत के लिये आजादी से लेकर आज तक राष्ट्र निर्माण का सफर जरा भी आसान नहीं रहा है और इन सभी चुनौतियों के बावजूद भारत नें पूरे राष्ट्र को एकजुट रखने की भूमिका बखूबी निभाया है।

उत्तर–पूर्व भारत में विप्लव को कम करने में सरकार की भूमिका– पूर्वोत्तर भारत में विप्लव के मुद्दे से निपटने में सरकार की भूमिका बहुआयामी है। केन्द्र और राज्य सरकारें कानून और व्यवस्था बनाये रखने, विकास को बढावा देने और प्रभावित क्षेत्रों की शिकायतों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

सरकार प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और कानून प्रवर्तन बनाये रखने के लिये जिम्मेदार है। इसमें विद्रोही गतिविधियों का मुकाबला करने, उग्रवाद विरोधी अभियान चलाने और नागरिक आबादी की सुरक्षा के लिये पुलिस और अर्द्वसैनिक कर्मियों जैसे सुरक्षा बलों को तैनात करना शामिल है।

सरकार उन सामाजिक–कार्मिक मुद्दों के समाधान के लिये विकास पहलों पर ध्यान केन्द्रित करती है जो अक्सर विप्लव को बढ़ावा देने वाली शिकायतों में योगदान करते हैं। इसमें बुनियादी ढांचे का विकास, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और क्षेत्र में जीवन के समग्र मानक में सुधार शामिल है।

सरकार संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिये विद्रोही समूहों के साथ बातचीत और शांति वार्ता में संलग्न हो सकती है। इन वार्ताओं का उद्देष्य विद्रोह के मूल कारणों को सम्बोधित करना और स्वायत्ता, विरोध स्थिति या शांति समझौतों सहित राजनीतिक समाधानों की दिशा में काम करना है।

सरकार प्रभावित क्षेत्रों की चिंताओं को दूर करने के लिये एक कानूनी और राजनीतिक ढांचा स्थापित करने के लिये जिम्मेदार है। इसमें कानूनों में संशोधन करना, विशेष दर्जो या स्वायत्ता प्रदान करना और लोकतांत्रिक संस्थानों के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करना शामिल हो सकता है।

सुझाव

रोजगार के मौके उपलब्ध कराकर कार्मिक स्थिति को मजबूत किया जा सकता है, जिससे वहाँ के निवासी तथा सरकार के मध्य दूरियाँ खत्म होंगी। सभी जातीये समूहों के समावेशी विकास को प्राथमिकता दी जाये। शांति वार्ता को पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिये। सेना, अर्द्वसैनिक बलों और पुलिस बलों का उपयोग करते हुये सुरक्षा बल के संचालन को रोकथाम का अंतिम संकेत माना जाना चाहिये।

पूर्वोत्तर में नागरिक समाज समूहों ने क्षेत्र में संघर्ष प्रबंधन और समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उग्रवाद की समस्या को कम करने के लिये इन संगठनों को बढ़ावा देना आवश्यक है। क्षेत्र में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिये धार्मिक संगठनों का उपयोग करना चाहिये। क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल विकासात्मक परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र भिन्नताओं एवं जटिलताओं का क्षेत्र है। क्षेत्र में अधिकांश संघर्षो और विद्रोहों के पीछे मूल कारण असमान विकास, क्षेत्रीय अभाव, भ्रष्टाचार, राजनैतिक मतभेद, जातीय भेदभाव, आंतरिक उत्पीड़न, एकीकरण की कमी इत्यादि हैं। वास्तव में कई राज्यों में विद्रोही अभियानों में कमी देखी गयी है और विभिन्न वार्ताओं और युद्ध विराम समझौतों में काफी प्रगति हुयी है। लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद से सम्बन्धित मौतें इस तथ्य का प्रमाण है कि उग्रवाद लगातार जारी है। प्रतिस्पर्धा लक्ष्य वाले विद्रोही और जातीय समूहों की संख्या इतनी जल्द कम होने वाली नहीं है, बल्कि और नये विद्रोही समूहों के उभरने की सम्भावना है। उग्रवाद सम्बन्धी गतिविधियों से निपटने के लिये एक विस्वसनीय और विरामात्मक रणनीति प्रदान करने की आवश्यकता है। यह निश्चित रुप से क्षेत्र में शांति प्रक्रिया को बढ़ावा देगा और केन्द्र में विश्वास बनाने के अवसरों को और विस्तृत करेगा।

संदर्भ

1. गुप्ता, एस. (2017), इंसरजेंसी इन नार्थईस्ट इण्डियाः अ कम्पेरेटिव एनालिसिस, रूटलेज
2. महंत, एन. (2016), इंसरजेंसी, काउन्टरइंसरजेंसी एंड द सिक्यूरिटी डिलेमा इन नार्थईस्ट इण्डिया, स्प्रिंगर

3. सिंह, डी.एस. (2015), नक्सलिज्मः अ कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस
4. जोशी, एम., और रोज़, एस.डी. (एडिटर), (2019), द इवाल्विंग चौलेंजेज ऑफ टेरोरिज्म एंड इंसरजेंसी इन द एशिया–पैसिफिक रीजन, पालग्रेव मैकमिलन
5. बरुआ, एस. (2016), इंडिया अगेंस्ट इटसेल्फः असम एंड पॉलिटिक्स ऑफ़ नेशनालिटी, पेंसिल्वेनिया युनिवर्सिटी प्रेस।
6. रॉय, एस.आर. (2019), इंसरजेंसी एंड काउन्टरइंसरजेंसी इन साउथ एशियाः थ्रो अ पीसबिल्डिंग लेंस, रूटलेज
7. बनर्जी, एम. (2017), सिक्यूरिटी एंड इंसरजेंसी इन इंडियाः अ केस–स्टडी ऑफ नागालैंड, टेलर एंड फ्रांसिस
8. गांगुली, एस. (2019), कनफ्लिक्ट अनइंडिंगः इंडिया–पाकिस्तान टेंसंस सिंस 1947, कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस।
9. डेका, एम.जे. (2014), इंसरजेंसी इन नार्थईस्ट इण्डियाः अ क्वेस्ट फॉर पीस, विज बुक्स इंडिया
10. चौधरी, जी. (2018), एथनिसिटी– इंसरजेंसी नेक्ससः अ केस स्टडी ऑफ यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा), रूटलेज